भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1922
बुधवार, 5 अगस्त, 2026 (14 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण

1922 श्री राजीब भट्टाचार्जीः
श्री सामिक भट्टाचार्यः
रेखा शर्माः
श्रीमती माया नारोलियाः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री राजेश परमानंद शुक्ला
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
श्री कणाद पुरकायस्थः
श्री सुभाष बरालाः
श्री संजय भाटियाः
श्री राजिन्दर गुप्ताः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "सहकार से समृद्धि" दृष्टिकोण के अंतर्गत, पूर्व में उक्त सुविधाविहीन ग्राम पंचायतों में, नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस), डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या आदर्श उप-नियमों को अपनाने से प्राथमिक समितियाँ अपने प्रचालनात्मक दायरे को सेवा प्रदायगी के विविध क्षेत्रों तक विस्तारित करने में सफल रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों में, जहाँ इसकी मौजूदगी अपेक्षाकृत कम है, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और सहकारी आंदोलन के पुनर्जीवन हेतु कौन-कौन सी विशिष्ट कार्यनीतियाँ तैयार की गई हैं ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) वर्ष 2023 से दिनांक 15.07.2026 तक पहले से असेवित ग्राम पंचायतों में नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों (पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना में 'सहकार से समृद्धि' परिकल्पना के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति **संलग्नक- 'क'** के रूप में संलग्न है।

(ख) और(ग) पंचायत/ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को जीवंत आर्थिक संस्थाओं के रूप में रूपांतरित करने तथा उनके व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के उद्देश्य से, आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधन करके पैक्स द्वारा अपनाए जाने हेतु परिचालित की गई थीं । आदर्श उपविधियां पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को शुरू करने में सक्षम बनाते हैं, जिनमें कस्टम हायरिंग सेंटर, डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, अन्न प्रापण, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कार्यकलाप, कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) आदि शामिल हैं ।

आदर्श उप-विधियों को अपनाने से बहुउद्देशीय पैक्स अब कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, टिलर्स आदि जैसी कस्टम हायरिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं । बहुउद्देशीय पैक्स में स्थापित ये कस्टम हायरिंग सेंटर किसान सदस्यों को आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करते हैं, जिससे उनके कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि हो रही है।

आदर्श उप-विधियों को अपनाकर, पैक्स अब बहु-सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने, अपने परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों किसान सदस्यों को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं आदि प्रदान करने में सक्षम हैं । यह पैक्स को आर्थिक कार्यकलापों के विविधीकरण और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत उत्पन्न करने में भी सक्षम बनाता है।

ये पहलें सहकारी आंदोलन को सशक्त करने में भी मदद करती हैं, क्योंकि इनसे पैक्स देश भर के किसान सदस्यों को अपने उत्पादों के विपणन और बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करने, पंचायत/ग्राम स्तर पर ही ऋण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उनके लिए आय के बहुविध एवं स्थिर स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनते हैं ।

(घ) सरकार ने क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने तथा उन राज्यों एवं क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक लक्षित रणनीति अपनाई है, जहां सहकारी कवरेज तुलनात्मक रूप से कम है । नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से अनाच्छादित ग्राम पंचायतों तथा गांवों को चिह्नित किया जा रहा है, तथा चरणबद्ध तरीके से नई समितियों की स्थापना की जा रही है । दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 10,230 एम-पैक्स सहित कुल 38,138 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

पहाड़ी, पूर्वोत्तर और अन्य भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें निर्माण लागत और सब्सिडी सहायता की उच्चतर स्वीकार्य सीमाएं, साथ ही विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता के शिथिल मानदंड शामिल हैं, ताकि ऐसे क्षेत्रों की छोटी सहकारी समितियां भी अवसंरचना विकास पहलों में भाग ले सकें ।

विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नए क्षेत्रीय एवं उप-कार्यालयों के माध्यम से संस्थागत पहुंच का विस्तार किया गया है। अनाच्छादित क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के दायरे में लाने के लिए सदस्यता और आउटरीच अभियान आयोजित किए जाते हैं।

श्वेत क्रांति 2.0, नई डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना, बहुउद्देशीय पैक्स का विकास, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से पेशेवर प्रशिक्षण, तथा विपणन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के लिए सहायता जैसे क्षेत्र-विशिष्ट पहलों का उद्देश्य कम विकसित क्षेत्रों में सहकारी समितियों की व्यवहार्यता में सुधार करना है ।

***

संलग्नक-क

वर्ष 2023 से दिनांक 15.07.2026 तक पंजीकृत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), डेयरी सहकारी समितियों और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2026-27			समग्र
		पैक्स	डीसीएस	एफसीएस	पैक्स	डीसीएस	एफसीएस	पैक्स	डीसीएस	एफ सीएस	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	11	0	1	0	0	0	0	14
2	आंध्र प्रदेश	0	895	2	11	172	0	0	0	0	1,080
3	अरुणाचल प्रदेश	126	17	21	10	8	7	0	0	1	190
4	असम	189	430	51	376	279	36	15	16	2	1,394
5	बिहार	56	2,710	1	1	1,788	1	4	0	0	4,561
6	छत्तीसगढ़	0	245	267	482	105	54	35	11	15	1,214
7	गोवा	23	3	2	15	2	2	0	0	0	47
8	गुजरात	447	592	16	186	208	10	29	10	0	1,498
9	हरियाणा	21	130	5	18	59	1	1	8	0	243
10	हिमाचल प्रदेश	88	431	6	44	415	4	4	8	2	1,002
11	जम्मू और कश्मीर	112	1,125	34	117	209	4	3	5	2	1,611
12	झारखंड	45	160	99	0	136	113	0	4	15	572
13	कर्नाटक	203	830	39	59	426	13	3	8	0	1,581
14	लद्दाख	3	3	1	0	0	0	0	0	0	7
15	लक्षद्वीप	0	0	7	0	0	22	0	0	0	29
16	मध्य प्रदेश	182	564	182	498	726	67	0	59	6	2,284
17	महाराष्ट्र	132	901	141	80	316	26	0	6	0	1,602
18	मणिपुर	84	21	69	43	6	2	0	0	0	225
19	मेघालय	223	16	7	43	1	11	24	0	1	326
20	मिजोरम	32	2	2	65	0	0	0	0	0	101
21	नागालैंड	7	4	14	43	1	5	0	0	0	74
22	ओडिशा	1,533	0	37	6	1,006	24	0	3	0	2,609
23	पुदुचेरी	2	2	3	2	1	0	0	0	0	10
24	पंजाब	0	328	17	132	689	35	21	10	0	1,232
25	राजस्थान	977	1,760	11	767	1,448	16	259	87	4	5,329
26	सिक्किम	24	55	0	1	22	4	2	0	0	108
27	तमिलनाडु	27	612	26	0	328	7	0	0	3	1,003
28	तेलंगाना	0	109	102	0	57	0	0	0	0	268

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2026-27			समग्र
		पैक्स	डीसीएस	एफसीएस	पैक्स	डीसीएस	एफसीएस	पैक्स	डीसीएस	एफसीएस	
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	0	1	0	0	0	0	0	0	6
30	त्रिपुरा	129	2	13	162	0	13	3	0	0	322
31	उत्तर प्रदेश	273	1,818	331	1,045	2,525	179	46	107	4	6,328
32	उत्तराखंड	530	91	104	76	178	20	0	0	0	999
33	पश्चिम बंगाल	22	124	0	3	117	3	0	0	0	269
34	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		**5,496**	**13,981**	**1,622**	**4,285**	**11,229**	**679**	**449**	**342**	**55**	**38,138**